. (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मिनिस्टर से बात करें।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO: So, this is the status of the ICAR. Therefore, the Government should concentrate more on the farmers as today we are importing nearly Rs.50,000 crore worth of pulses, oil seeds. Now, the Government has initiated the Horticulture Mission. But we are losing nearly Rs.45,000 crore worth of vegetables and horticulture produce by destroying them. So, these three sectors have to be looked into properly. If they want to do the Horticulture Mission in true spirit, then let them please tell the Food Processing Ministry to create additional facility of storage, cold storage, food preservation and all the other things which are required so that the farmers get their actual price for their produce.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up matters of urgent public importance.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन - अनुपस्थित।

श्री शैलेन्द्र कुमार।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शून्य प्रहर में सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, इस वक्त संपूर्ण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से वही व्यक्ति मरता है जिसके पेट में भोजन नहीं होता, जिसका पेट खाली होता है। इसमें तमाम खेतिहर मज़दूर भी आते हैं। आज लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि शहरों में ज्यादातर मज़दूर वहां पर खड़े मिलते हैं जिसका नाम लेबर चौराहा होता है। वे रोज़ कमाकर खाने वाले लोग हैं। रात में ज्यादातर ये लोग पुलों के नीचे पटरियों पर या पेड़ के नीचे अपना गुज़ारा करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे मज़दूरों के लिए रैन बसेरा बनाए जाएं जहां वे अपना सिर छिपा सकें। खासकर दिल्ली में हमने देखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा कामगार मजदूर रोज़ी कमाने के लिए आते हैं, उनको रैन बसेरा की स्विधा दी जाए। रैन बसेरा में जो तमाम अन्य स्विधाएं मिलती हैं, वहां पर जो उनको गद्दा और रजाई दी जाती है उसके लिए उनसे पैसे लिये जाते हैं, इस बात की भी जांच कराई जाए। इसके अलावा जगह-जगह अलाव जलाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा तत्काल की जानी चाहिए। वन विभाग के पास लकड़ियों की भरमार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हं कि वन विभाग द्वारा लकड़ियों की व्यवस्था कर चौराहों पर अलाव जलाई जाए तथा ज़रूरतमंदों को कंबल भी बांटे जाएँ ताकि वे मज़दूर ठंड से अपनी जान बचा सकें। उन्हें कम्बल भी बांटें जाएं, ताकि गरीब लोग ठंड से बच सकें। उत्तर प्रदेश से भी सूचना मिली है कि कम से कम 15-16 लोग ठंड से मर गए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाह्ंगा, खास कर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और शहरी विकास मंत्री से ग्जारिश करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर जनपद का मुख्यालय है, शहरी विकास मंत्रालय का मुख्यालय है, जहां तहसील का मुख्यालय है, ब्लाक का मुख्यालय है या बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर रैन बसेरा बनाने की कृपा करें ताकि खेतिहर और रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, वे ठंड से बच सकें और अपना पेट भर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सिर्फ दो-दो मिनट का समय लें, क्योंकि सदस्यों की बह्त लम्बी-चौड़ी लिस्ट है।

> Shri Tek Lal Mahto - not present. Shri Dharmendra Pradhan - not present.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, the Regional Cancer Centre functioning at Trivandrum is a prestigious institution. They are doing research work. So far as treatment of patients is concerned, it is very satisfactory. Considering the development of health attained in this field, it is a fit institution to be transformed into a deemed university. I would request not only to the University Grants Commission but also to the Government and the Minister of Human Resource Development to give instruction to the UGC for giving recognition as a deemed university to the Regional Centre at Trivandrum.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chhattar Singh Darbar - not present.

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान में मुंगफली की फसल की सरकारी खरीद नहीं होने के कारण, मुंगफली उत्पादक किसानों की समस्या व उनमें पनपे असंतोष व आक्रोश की ओर दिलाना चाहता हं।

यद्यपि मुंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1520 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो हर हालत में किसान की अपेक्षाओं से कम है। मगर दुर्भाग्य यह है कि न्यूनतम मूल्य पर सरकारी खरीद नहीं हो पाने के कारण 1000 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से व्यापारियों को बेचना पडता है।

राजस्थान के बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, नागौर, गंगानगर सहित ज्यादातर रेगिस्तानी जिलों में कृषि विभाग के तिलहन उत्पादन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत